

प्रेषक,

सुशांत पटनायक,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 20 सितम्बर, 2010

विषय :- अनुदान संख्या-27 में राज्य सेक्टर के आयोजनागत पूंजीगत पक्ष में "वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण" योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-1925/3-5 दिनांक 05 जून, 2010 के परिप्रेक्ष्य में शासन के पत्र संख्या-184/X-2-2010-12(45)/2005 दिनांक 24 जून, 2010 के क्रम में आपके कार्यालय के प्रस्ताव/पत्र संख्या नि-118/3-5 दिनांक 24 जुलाई, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पूंजीगत पक्ष की "वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण" योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्त विभाग द्वारा व्यक्त की गयी सहमति की सीमा रु0 1,50,00,000/- (रु0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) तक आपके द्वारा उक्त वर्णित प्रस्ताव दिनांक 24 जुलाई, 2010 के साथ उपलब्ध करायी गयी सूची (संलग्नक-2) में उल्लिखित कार्यों में से शीर्ष प्राथमिकता धारित करने वाले कार्यों के लिए रु0 1,50,00,000/- (रु0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग पृथक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू याजेनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनाएँ एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रव्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फौल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेंजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
7. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. जो निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXXVII(1)/2009 दिनांक 16 जुलाई द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. मासिक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
11. धनराशि का आहरण/व्यय तथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक आवश्यक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
13. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्यों लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संचन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।
15. विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्रसहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परियोजना के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे। उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।
16. जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देखक प्रस्तुत किये जाय, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
17. यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात् योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
18. ऐसे सभी कार्य जो रु० 5.00 लाख से अधिक हैं, का आगणन/प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा ऐसे आगणन/प्राक्कलन के सापेक्ष शासन के टी०ए०सी० वित्त विभाग से परिणोपरान्त अनुमोदित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त ही इस प्रकार के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति अधीनस्थ कार्यालयों को निर्गत की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में आय-व्ययक अनुदान सं०-27 के लेखाशीर्षक 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परियोजना 01-वानिकी 101-वन संरक्षण और विकास 04-वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-69-A(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशान्त पटनायक)
अपर सचिव

संख्या- ~~ब-248~~ (1)/X-2-2009, तददिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.

(सुश्री पटनायक)
अपर सचिव